है कि एक इस साईड में है जहां पहलेजा है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं और दुसरी साईड में गुलजार बाग है, बीच में हाजीपुर आता है। इधर भी बनता है तो भी उतनी दूरी है, उधर भी बनता है तो भी इतनी दूरी है। इसलिये मैंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी और आपको मालूम है कि इस बजट में एक करोड़ 60 लाख रुपए उसके लिये दे दिया है और वह पुल के सर्वेक्षण के लिये नहीं बल्कि पुल का स्थल चयन करने के लिये और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि पहलेजा में नहीं बन रहा है, अब हमको डिस्कलोंज नहीं करना चाहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन के बाद जब रिपोर्ट आएगी और निर्णय होगा तो इनकी सारी गलत धारणाएं दूर हो जाएंगी।

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी: आखिर चाहते हैं आप बिहार में न जाए?

مولانا عبیداللہ خاں اعظمی: آخر چاہتے ہیں آپ بہار میں جائے۔

श्री एस० एस० अहलुवालिया: चुप रहो, तुम ससुराल में खड़े हो।

Vacancies in Railways

*482. SHRI JALALUDIN ANSAR1: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total number of vacancies which have arisen in Indian Railways in Group 'A' post (excluding Medical and RPF) on account of retirement/death etc. during the last three years, year-wise;

(b) the total number of Group 'A' posts created (excluding Medical and RPF) during the said period, year-wise;

(c) the total number of Group 'A'offic-ers sent on deputation etc. (excluding Medical and RPF) during the said period, year-wise:

(d) the number of officers directly re-cruited during the said period, year-wise; and

(e) the number of Group 'B' officers promoted to Group 'A' during the said period, year-wise?

रेल मंत्री (श्री रामविलास पासवान): एक विवरण सभापति पर रहा दिया गया है।

विवरण

(क) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1993 : 554
1994 : 556
1995 : 479

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1993 : 35
1994 : 09
1995 : 31

(ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1993 : 29
1994 : 41
1995 : 56

(घ) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1993 : 212
1994 : 174
1995 : 106

(ड) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1993 : 185
1994 : 113
1995 : 12

श्री जलालुदीन अंसारी: सभापति महोदय, ग्रुप "ए" अफसरों की बहाली का दो तरीका है। एक तरीका डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो पी०सी०एस०यू०सी० के जरिए होगा और इसमें 60 परसेंट ग्रुप "ए" के आफिसर की बहाली होगी, दूसरा है ग्रुप "बी" से ग्रुप "ए" में 40 परसेंट वेकेंसीज को भरने का है। यह एड्हॉक अरेंजमेंट है "बी" ग्रुप" से "ए" ग्रुप में ले जाने का। इस संबंध में एक दूसरे पहलू की ओर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि डी०पी०एस० के जरिए ग्रुप "बी" के आफिसर को ग्रुप "ए" में प्रमोट करने की जो कार्रवाई होनी चाहिये वह समय पर नहीं होती है। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वह यह कि इस तरह का इंस्ट्रक्शन पहले भी था कि इनको रेग्यूलराइज किया जाए और आम तौर पर यह एड्हॉक अरेंजमेंट दो-तीन महीने के लिये हुआ करता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 साल से 10 साल तक लोग एड्हॉक पर काम कर रहे हैं जबकि 1995 में भी तत्कालीन माननीय रेल मंत्री ने यह आदेश दिया था कि डी०पी०एस० के जरिये जिनके सेवा 3 साल की हो चुकी है उनको ग्रुप "बी" से ग्रुप "ए" में प्रमोट किया जाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस आदेश का पालन प्रति वर्ष प्रमोशन के सिलसिले में "ए" ग्रुप और "बी" ग्रुप में क्यों नहीं किया जाता है? उन्होंने आंकड़े दिये हैं लेकिन वह आंकड़े पिछले कई वर्षों को मिला करके उसको ईयर-वाईज कर देने से ...**(व्यवधान)**

श्री सभापति: प्लीज कांकलूड।

श्री जलालुदीन अंसारी: इसीलिये हम कहना चाहते है कि इसकी वजह से प्रमोशन का जो तरीका है, वैसे आफसर अभी दो हजार है जो एड्हॉक बेसिस पर 5 साल से 10 साल तक चले आ रहे हैं और जो सीधे रिक्रूमेंट में आए वह प्रमोशन पाकर बड़े आफिसर हो जाते हैं। ऑपरेशनल वर्क में एड्हॉक वाले काम कर रहे हैं। तो इससे उनके काम की एफिशिएंसी भी घटती है। इसलिये हम चाहेंगे कि यह जो 1989 का रेलवे बोर्ड का 3 से 5 वर्ष में प्रमोट करने का जो इंस्ट्रक्शन था उसका भी पालन नहीं किया गया। और फिर तत्कालीन रेल मंत्री जी ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थीं, उनका भी पालन नहीं किया गया। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि प्रति वर्ष रेगुलराईजेशन का जो यह सिलसिला है, इसको कार्यान्वित करने में रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय को क्या कठिनाई है?

†[شری جلال الدین انصاری: ادھیکش مہودے
گروپ "اے" افسروں کے بحالی کے دو طریقے ہیں
ایک طریقہ ڈیکرو ٹمنٹ سے جو پی۔ سی۔ ایس
کے ذریعہ ہوگا۔ اور اس میں ۶۰ فیصد گروپ
"اے" کے آفیسری بحالی ہوگی دوسرا ہے گروپ
"بی" سے گروپ "اے" میں ۴۰ فیصد ویکینسیز
کو بھرنے کا ہے۔ یہ ایڈھاک ارینجمنٹ ہے "بی"
گروپ سے "اے" گروپ میں لے جانے کا۔ اس
سمبندھ میں ایک دوسرے پہلو کی اور
دھیان دلانا چاہتے ہیں کہ کئی بی ایس
کے ذریعہ گروپ "بی" کے آفیسرز کو گروپ
"اے" میں پروموٹ کرنے کی جو کاروائی ہونی
چاہیئے وہ وقت پر نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات
جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح
کا انسٹرکشن پہلے بھی تھا۔ کہ انکو ریگولرائز
کیا جائے اور عام طور پر یہ ایڈھاک ارینجمنٹ
دو تین مہینے کیلئے ہوا کرتا تھا۔ لیکن میں آپکو
بتانا چاہتا ہوں کہ پانچ سال سے دس سال
تک لوگ ایڈھاک پر کام کر رہے ہیں جبکہ
1995 میں بھی تتکالین مانیہ ریل منتری
نے یہ آدیش دیا تھا کہ ڈی۔ پی۔ ایس کے
ذریعہ جنکی سیوا تین سال کی ہو چکی ہے انکو
گروپ "اے" سے گروپ "بی" میں پروموٹ کیا
جائے۔ میں آپکے مادھیم سے منتری جی سے

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न से थोड़ा हटकर यह इन्फॉरमेशन मांगी है इसलिये इस समय मेरे पास इसका जवाब तैयार नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो ऐडहॉकिज्म का सवाल है, मैंने स्वंय इस मामले को देखा है। जो रिक्तियां हैं वे 1993 में 554 हैं, 1994 में 556 हैं और 1995 में 479 हैं। जो रिक्तियां सीधी भर्ती और प्रमोशन के माध्यम से भरी गई हैं वे 1993 में 212, 1994 में 174 और 1995 में 106 हैं। प्रोन्नति के माध्यम से 1993 में 185, 1994 में 13 और कोर्ट केस के कारण 1995 में 12 रिक्तियां भरी गई हैं। तो ऐडहॉक के आधार पर काफी बड़ी संख्या में ऐब्सार्ब करने का काम किया गया है। हम स्वयं इस दिशा में प्रत्यनशील हैं कि ऐडहॉकिज्म ज्यादा ने चले और जितनी जल्दी हो सके उसमें रेगुलराईज करने का काम होना चाहिये लेकिन उसके लिये जो नियम हैं, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि डी०पी०सी० ग्रुप "बी" से ग्रुप "ए" में प्रमोशन के लिये बिठाई जाती है इन सब चीजों के बावजूद इसमे समय ज्यादा लग रहा है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं और हम देखेंगे कि इसमें समय ज्यादा ने लगे और रेयुलराईजेशन का काम जल्दी से जल्दी हो सके।

श्री जलालुदीन अंसारी: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अभी भी ग्रुप "बी" में करीब 2,000 आफिसर्स सीनियर स्केल में ऐडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं और लगभग 800 लोग तो 5 साल से ऐडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो यह जो रेगुलराईज करने का सवाल है, हम चाहेंगे कि मंत्री जी आश्वासन दें कि वह रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया को तेज करेंगे। दूसरा आश्वासन हम यह चाहते हैं कि डी०पी०सी० की बैठक समय पर हो और उसके माध्यम से ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" के लिये रिक्रूटमेंट की कार्यवाही की जाए। इसी तरह जो डॉयरेक्शंस पिछले मंत्रियों ने दी थीं, उनका पालन किया जाए ताकि रेलवे कर्मचारियों को प्रमोशन का बैनिफिट मिल सके, रिटायरमेंट का बैनिफिट मिल सके और दूसरे बैनिफिट मिल सकें। इससे उनके काम में भी ऐफिशियेंसी आएगी। इसलिये हम चाहते हैं कि इनका रेगुलराइजेशन प्रमोशन के मैथड के अनुसार किया जाए।

श्री जलालुदीन अंसारी: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अभी भी ग्रुप "बी" में करीब 2,000 आफिसर्स सीनियर स्केल में ऐडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं और लगभग 800 लोग तो 5 साल से ऐडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो यह जो रेगुलराईज करने का सवाल है, हम चाहेंगे कि मंत्री जी आश्वासन दें कि वह रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया को तेज करेंगे। दूसरा आश्वासन हम यह चाहते हैं कि डी०पी०सी० की बैठक समय पर हो और उसके माध्यम से ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" के लिये रिक्रूटमेंट की कार्यवाही की जाए। इसी तरह जो डॉयरेक्शंस पिछले मंत्रियों ने दी थीं, उनका पालन किया जाए ताकि रेलवे कर्मचारियों को प्रमोशन का बैनिफिट मिल सके, रिटायरमेंट का बैनिफिट मिल सके और दूसरे बैनिफिट मिल सकें। इससे उनके काम में भी ऐफिशियेंसी आएगी। इसलिये हम चाहते हैं कि इनका रेगुलराइजेशन प्रमोशन के मैथड के अनुसार किया जाए।

श्री जलालुदीन अंसारी: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अभी भी ग्रुप "बी" में करीब 2,000 आफिसर्स सीनियर स्केल में ऐडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं और लगभग 800 लोग तो 5 साल से ऐडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो यह जो रेगुलराईज करने का सवाल है, हम चाहेंगे कि मंत्री जी आश्वासन दें कि वह रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया को तेज करेंगे। दूसरा आश्वासन हम यह चाहते हैं कि डी०पी०सी० की बैठक समय पर हो और उसके माध्यम से ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" के लिये रिक्रूटमेंट की कार्यवाही की जाए। इसी तरह जो डॉयरेक्शंस पिछले मंत्रियों ने दी थीं, उनका पालन किया जाए ताकि रेलवे कर्मचारियों को प्रमोशन का बैनिफिट मिल सके, रिटायरमेंट का बैनिफिट मिल सके और दूसरे बैनिफिट मिल सकें। इससे उनके काम में भी ऐफिशियेंसी आएगी। इसलिये हम चाहते हैं कि इनका रेगुलराइजेशन प्रमोशन के मैथड के अनुसार किया जाए।

گروپ "بی" میں قریب ۲۰۰۰ آفیسرز سینئر اسکیل میں ایڈہاک بیسز پر کام کر رہے ہیں اور لگ بھگ ۸۰۰ لوگ تو پانچ سال سے ایڈہاک بیسز پر کام کر رہے ہیں تو یہ ریگولرائز کرنے کا سوال ہے ہم چاہیں گے منتری جی اشوراسن دیں کہ وہ ریگولرائزیشن کی پراکریا کو تیز کریں گے دوسرا اشوراسن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈی۔پی۔سی کی بیٹھک وقت پر ہو اور اسکے مادھیم سے گروپ "اے" اور گروپ "بی" کے لئے ریکروٹمنٹ کی کارروائی کی جائے۔ اسی طرح جو ڈائریکٹنس پہلے منتری جی نے دیں تھیں۔ انکا پالن کیا جائے۔ تاکہ ریلوے کرمچاریوں کو پروموشن کا بینیفٹ مل سکے۔ ریٹائرمنٹ کا بینیفٹ مل سکے اور دوسرے بینیفٹ مل سکیں۔ اس سے انکے کام میں بھی ایفی شینسی آئے گی اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ریگولرائزیشن پروموشن کے میٹھڈ کے مطابق کیا جائے۔

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, इन्होंने, 3 आश्वासन मांगे हैं। पहला आश्वासन इन्होंने यह मांगा है कि डी०पी०सी० की बैठक समय पर होनी चाहिए। हम देखेंगे कि डी०पी०सी० की बैठक समय पर हो और आवश्यक कार्यवाही हो। दूसरा, माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस संबंध में जो प्रोविसस मिनिस्टर्स की डायरेक्शंस हैं उनको लागू करवाया जाए। हम निश्चित रूप से इस दिशा में कार्यवाही करेंगे। तीसरा इन्होंने ऐडहॉकिज्म का सवाल उठाया है। अभी इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हम अपने अधिकारियों से बातचीत करके देखेंगे कि इसकी कुछ समय सीमा बांधी जाए।

श्री मूलचन्द मीणा: महोदय, रेलवे विभाग में शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब के कर्मचारियों के साथ, चाहे वह सीधी भर्ती के अनुसार हों या पदोन्नति के अनुसार हों, जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वह निराशाजनक है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1993—95 तक तीन साल के अंदर समूह "ख" और समूह "क" में जो 310 अधिकारियों की पदोन्नति की गयी थी, उनमें कितने शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के अधिकारी थे और क्या वह आरक्षण कोटे के अनुसार सही है? उदाहरण के तौर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पश्चिमी रेलवे के अंदर मुम्बई के अंदर सीनियर स्केल के अधिकारियों के प्रमोशन के समय अनुसूचित जाति के अधिकारियों के साथ सही न्याय नहीं हुआ है। वहां शैडयूल्ड कास्ट के 86 के बैच के अधिकारी का प्रमोशन न करके जनरल कास्ट के 87 के बैच के अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। शैडयूल्ड कास्ट के अधिकारियों को वहां के चीफ इंजीनियर एक-एक महीने के लिए कभी अहमदाबाद भेज देते है, कभी बीकानेर भेज देते हैं और कभी जयपुर भेज देते हैं तथा इस प्रकार से उनका हैरसमैंट करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स का जो आरक्षण है, चाहे वह सीधी भर्ती से हो या पदोन्नति से हो, उसको आप कब तक पूरा कर देंगे? दूसरे में यह भी कहना चाहूंगा कि शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के "सी" और "डी" श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा ले ली गयी, उसका रिजल्ट भी निकाला गया किन्तु उन्हें आज तक नियुक्त नहीं किया गया है। क्या मंत्री जी उनको नियुक्ति देंगे? ऐसा जालंधर और पटना के अंदर हुआ है कि उनकी परीक्षा लेने के बाद, रिजल्ट निकालने के बावजूद उनको नौकरी नहीं दी गयी। तो मैं जानना चाहूंगा कि शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों के साथ सीधी भर्ती और पदोन्नति के आरक्षण के संबंध में जो अन्याय हो रहा है, उसको मंत्री महोदय कैसे और कब तक दूर करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, अभी शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं है किन्तु माननीय सदस्य को मैं वह आंकड़े भेज दूंगा और सदन के पटल पर भी रख दूंगा। जहां तक शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स का सवाल है, तो इस संबंध में हम बहुत सतर्क हैं और जिस दिन हमने रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से पद भार संभाला, उसी दिन मैंने

अधिकारियों की बैठक बुलाकर स्पष्ट आदेश दिये कि चाहे प्रमोशन का मामला हो, चाहे नियुक्ति का मामला हो, आज अमारे सामने कुछ वैधानिक कठिनाइयां है जैसे स्टॉल वगैरह चल रहे हैं, फ्रूट स्टॉल्स का मामला है, इस संबंध में कोर्ट में मामले चल रहे हैं, अदरवाइज इन सारी चीजों में हम चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन का कोटा है, उसके मुताबिक शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को सहुलियतें दी जाएं। हमने यहां तक रिटन में आदेश दिया है कि विदेश में बड़ी संख्या में हमारे आफिसर्स जाते हैं तो उनमें कितने शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के आफिसर्स होते हैं। मेरे पास जो फाइलें आती थीं, उनमें से कई फाइलों को मैंने लौटा दिया और लिखित में क्वायरी की कि विदेश जाने वाले अधिकारियों में कौन-कौन से अधिकारी शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के हैं और मुझे खुशी है कि जब जो फाइलें आ रही हैं, उसमें उनके नाम शामिल हैं हमने यह भी कह दिया है कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारी की जो सी०आर० लिखी जाती है और अगर वह उसके खिलाफ है, या एडवर्स रिपोर्ट है तो वह केवल मिनिस्टर के अप्रूवल से होगी। हम यह चाहते है कि विभाग में अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो और अगर कोई अनुसूचित जाति और जनजाति का कर्मचारी या अधिकारी अथवा किसी भी जाति का अधिकारी अनुशासन को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए लेकिन यदि हमें यह देखने को मिले कि कास्ट के आधार पर दुर्भावना से ग्रसित होकर कास्ट लाइन पर किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गयी है या उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी है तो उस संबंध में हम कार्यवाही करेंगे। तो कहीं भी आरक्षण के कोटे का सवाल हो या प्रमोशन में उनके प्रतिनिधित्व का सवाल हो, उनके स्टॉल्स वगैरह हैं, वहां उनके अधिकार का सवाल हो या और कही भी उनके कांस्टीट्यूशनल राइट्स का सवाल हो, उस संबंध में हमने बहुत कड़ाई से हिदायतें जारी कर दी हैं और न केवल जारी की हैं बल्कि हम उनका कड़ाई से पालन भी कर रहे है। हम आपको बतलाना चाहते हैं कि पहली बार जो रिक्रूटमेंट बोर्ड का चेयरमैन है, चाहे पटना का चेयरमैन हो या इलाहाबाद का चेयरमैन बना हो, वह शैडयूल्ड कास्ट से बने हैं। रांची में भी जो चेयरमैन बना है तो हमने कहा कि यह ट्राइबल इलाका है, शैडयूल्ड कास्ट का इलाका है, इस वर्ग के व्यक्ति को ही बनना चाहिए।

माइनोरिटी के लोगों को हम बना रहे है, महिलाओं को हम बना रहे हैं। हम एस०सी०,एस०टी०, माइनोरिटीज और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे। जहां तक एस०सी०,एस०टी० का सवाल है उसमें तो कम्प्रोमाइज करने का सवाल ही नहीं है। उनका कांस्टीट्यूशनल राइट बनता है, चाहे राम विलास पासवान रेल मंत्री बने यह्वा कोई दूसरा रेल मंत्री बने।

श्री मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: सर, हमें मंत्री जी के इस सवाल से बेहद खुशी हुई है कि वे एस०सी०,एस०टी० के लोगों के रिजर्वेशन के सिलसिले में बहुत सतर्क हैं और जो भी मंत्री आगे रेल मंत्री होगा उसे भी सतर्क रहना चाहिये। हम यह जानना चाहते हैं कि जो हालत एस०सी०एस०टी० की है उससे ज्यादा बदतर हालत मुसलमानों की है और उसी के साथ-साथ सारी माइनोरिटीज की है। चूंकि हुकूमत भी यही कहती रही है कि माइनोरिटीज का परसन्टेज् बहुत कम है और उनके साथ किसी में भी इंसाफ नहीं किया गया। सर, रेलवे एक बहुत बड़ा महकमा है और इस महकमे के जरिये माइनोरिटीज के साथ जो इंआफों दीगार हुई हैं इसमें बहुत हद तक उसकी तलाशी की जा सकती है। मैं उस सवाल से लगे हुए उस हिस्से को पूरा करना चाहता हूं कि बी और ए ग्रुप में जो लोग प्रमोट किये गये हैं उनमें दलित, बैकवर्ड और माइनोरिटीज के अधिकारियों की तादाद क्या है और साथ-साथ यह भी बता दीजिये कि ग्रुप बी और सी के कितने लोग रिटायर हुए है और उस जगह पर कितने लोगों की भर्ती हुई है तथा उसमें एस०सी, एस०टी०, ओ०बी०सी और माइनोरिटीज के लोगों की तादाद कितनी है? इस सिलसिले में सरकार माइनोरिटीज मुसलमानों के बारे में क्या सोच रही है और क्या उसका निशाना है जो उसे पूरा करने का इरादा रखती है?

†[शेख मौलाना अब्दुल्लाह खां आज़मी: सर, हमें मंत्री जी के इस सवाल से बेहद खुशी हुई है कि वे एस०सी०,एस०टी० के लोगों के रिजर्वेशन के सिलसिले में बहुत सतर्क हैं और जो भी मंत्री आगे रेल मंत्री होगा उसे भी सतर्क रहना चाहिये। हम यह जानना चाहते हैं कि

ایس ٹی کی ہے اس سے زیادہ بدتر حالت مسلمانوں کی ہے اور اسکے ساتھ ساتھ مائنارٹیز کی ہے۔ کیونکہ حکومت یہ کہتی رہی ہے مائنارٹیز کا پرسنٹیج بہت کم ہے اور اس کے ساتھ کسی نے انصاف نہیں کیا گیا۔ سر۔ ریلوے ایک بہت بڑا محکمہ ہے اور اس محکمے کے ذریعہ مائنارٹیز کے ساتھ جو انصافوں دیکھا ہوا ہے۔ اس میں بہت حد تک اس کی تلافی کی جا سکتی ہے میں اس سوال سے لگے ہوئے اس حصے کو پورا کرنا چاہتا ہوں کہ جی" اور "نے گروپ میں جو لوگ پرموٹ کئے گئے ہیں ان کو لیٹ ویک ورڈ اور مائنارٹیز کے اوھیکاروں کی تعداد کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ گروپ بی اور سی کے کتنے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں اور اس جگہ پر کتنے لوگوں کی بھرتی ہوئی ہے اور اس میں ایس سی ایس ٹی اور او بی سی اور مائنارٹیز کے لوگوں کی تعداد کتنی ہے اس سلسلہ میں سرکار مائنارٹیز مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور کیا اسکا نشانہ ہے جو اسے پورا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔]

श्री राम विलास पासवानः सर, जहां तक एस०सी०, एस०टी० का सवाल है उनका तो एक रिजर्वेशन का मामला है और कंस्टीट्यूशन का अधिकार है लेकिन मंडल कमीशन के बाद बैकवर्ड क्लासेज का भी अधिकार बना है। मंडल कमीशन के तहत जो माइनोरिटीज के लोग आते हैं उनकी भी सूची है लेकिन माइनोरिटीज की सूची संभवतः नहीं रखी जाती है। लेकिन सूची रखी जाती हो या न भी रखी जाती है जब हम कोई कमेटी बनाते हैं तो मैं जरूर इस बात को देखता हूं कि जो माइनोरिटी का अधिकारी है उस अधिकारी का या माइनोरिटी का सेंटीमेंट कहीं हर्ट न हो। इसके लिए जहां कहीं भी हमारे पास माइनोरिटी के अधिकारी, कर्मचारी या उम्मीदवार उपलब्ध हैं उनके संबंध में भी हम ध्यान देने का काम कर रहे हैं। चूंकि इसमें दो मत नहीं है कि जो माइनोरिटी की पॉपुलेशन है उसके अनुपात में सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या बहुत ही कम है। माननीय सदस्य ने केटेगरी वाइज विवरण मांगा है। साथ ही साथ यह भी मांग की है कि किस वर्ष कितनी नियुक्तियां हुई हैं और कितने लोगों को लिया गया है। हम माननीय सदस्य को दो-तीन साल का विवरण तो जरूर दे देंगे। हम कोशिश करेंगे कि तीन साल के जो हमारे फिगर्स हैं इनको लाकर हम सदन के पटल पर रखें। उसके बाद भविष्य में भी जैसा मैंने कहा मैं चिंतित रहूंगा। मैं भूत में भी चिंतित था वर्तमान में भी चिंतित हूं और भविष्य में भी चिंतित रहंगा। यह मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

SHRI JOHN F. FERNANDES: Mr. Chairman, Sir, the question is about filling up of vacancies in the Railways. Many hon. Members have also demanded zones to develop backward areas. My question is about the health of the Railways. I think Railways is one of the departments in our country which is heavily burdened with personnel—there are twenty lakh workers in the Railways. So, the more the personnel in the Railways, the greater is the element of pilferage and the more is the risk of loss to the Railways. Recently, we have computerised the railway system in India. In spite of computerisation, there is pilferage. Throughout the world, hi-tech and computers are being used in the Railways to increase efficiency and to earn profit for the organisation. May I know from the hon. Minister as to how much amount he has saved by way of non-employment of personnel on account of computerisation in the Railways?

श्री राम विलास पासवानः सभापति जी, यह बात सही है कि जब से कम्प्यूटराइजेशन हुआ है चार-पांच साल पहले रेलवे कर्मचारियों की संख्या सोलह लाख

कुछ हजार थी, वही संख्या कर्मचारियों की अब है। संसार जिस तेज गति से आगे चल रहा है उसमें रेलवे को अलग नहीं रख सकते है। आज के युग में जहां कम्प्यूटर के द्वारा रिजर्वेशन होता है तो हाथ से लिखकर रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता है। हमारे यहां आदमी की कमी नहीं है, दूसरे कंट्रीज में मैनपावर की कमी है, हमारे यहां मैनपावर ज्यादा है। मैनपवार के साथ-साथ जो इफीसियेन्सी का सवाल है, उस इफीसियेन्सी के सवाल को लेकर जितनी भी लेटेस्ट टेक्नालाजी हैं, उनका हर मिनिस्ट्री में उपयोग किया जा रहा है इसलिए उसमें रेलवे भी पीछे नहीं है और उसका हमको रिजल्ट भी मिल रहा है। मुझको कहना नहीं चाहिए लेकिन हमको पिछले तीन महीने के रेलवे के कार्य से संतोष है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यह रेलवे के लिए सबसे खराब मौसम आ रहा है और यह रेनी सीजन होता है, बरसात का समय होता है इसलिए यह रेलवे के लिए सबसे खराब पीरियड होता है। इस समय में अगर एक्सीडेंट हो जाये तो रेलवे मिनिस्टर की आधी जान तो निकल ही जाती है। अभी आठ दिन पहले जब पटना की बगल में एक घटना घटी तो सुबह चार बजे तक तो मैं सो नहीं पाया जब तक कि यह मालूम नहीं हो गया कि वहां किसी आदमी की जान को क्षति नहीं हुई है, कोई केजुअलिटी नहीं हुई है। सम्पत्ति की क्षति हो जाये तो वह बर्दाश्त हो जाती है लेकिन किसी की जान की क्षति हो जाये तो किसी भी सेंसेटिव रेलवे मंत्री को बर्दाश्त नहीं हो पाती है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले तीन महीने के अन्दर एक भी केजुअलिटी की घटना नहीं हुई है जबकि मार्च और अप्रैल के महीने में दर्जनों जगह पर घटनाएं हुई थीं। उसी तरीके से पंक्चुअलिटी का सवाल है, हम उसमें बहुत कड़ाई कर रहे हैं। बरसात के महीने में भी हम पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना चाहते हैं और हम ट्रेनों के एक्सीडेंट को भी अवाइड करना चाहते हैं। यदि आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो स्वाभाविक है कि जो नई-नई टेक्नालाजी आई है उससे हमारी स्टैथ प्रति वर्ष जितनी बढ़नी चाहिए थी, वह स्टैथ रेलवे की बढ़ी नहीं है। रेलवे में कर्मचारियों की जितनी पहले संख्या थी, उतनी ही अब है। लेकिन जिस तरीके से दूसरे पब्लिक सेक्टर घाटे में चल रहे हैं, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रेलवे उस तरह से घाटे में नहीं चल रहा है।

यदि हमारे सामने पब्लिक वैलफेयर का सवाल न हो, बैकवर्ड एरिया में रेलवे लाइन लगाने का मामला नहीं आता हो और सिर्फ मुनाफा कमाने का सवाल हो तो हम रेलवे को वहीं पर ले जायें जहां पर माल उपलब्ध हो और वहीं पर वैगन्स को भी ले जाने का काम करे तो रेलवे तो दो सौ परसेंट मुनाफे में काम करेगा। चूंकि हम काफी मुनाफा कमाते हैं और दूसरी तरफ नई रेलवे लाइनों के विकास के ऊपर और पैसेन्जर के ऊपर हम खर्चा भी करते हैं और जितनी भी रेल गाड़ियां पैसेन्जर के लिए चलती हैं वे सब घाटे में चलती हैं। इसको आप हिन्दुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में देख लीजिए। रेलवे के घाटे की पूर्ति हम माल ढोकर करते हैं। इसलिए रेलवे की दयनीय स्थिति का जो आपने चित्रण किया है, वैसी दयनीय स्थिति रेलवे की नहीं है। यदि रेलवे के पास अधिक से अधिक फंड हो तो हम चाहते हैं कि जो अधिक से अधिक रूरल एरियाज हैं, अविकसित एरियाज है, हम उनके विकास का काम कर सकें। लेकिन यदि हम अविकसित एरियाज को छोड़ दें, सिर्फ अपने रिसोर्सेज के ऊपर हम निर्भर रहे तो रेलवे को आज जितना मुनाफा हो रहा है उससे चार गुना मुनाफा होगा।

*483[The Questioner (Shri Aantray Dcvshankar davc) was absent. For answer vide Col...infra]

Procedure for Tender in Railways

*484. SHRI MD. SALIM:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there are any procedures for inviting tenders in the Railways;

(b) if so, when such procedures were laid down;

(c) whether there are cases of violation of these procedures; and

(d) if so, the details thereof?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां।

(ख) ये प्रक्रियाएं बहुत पहले से प्रचलित हैं। ये नियमों और प्रक्रियाओं के सारसंग्रह में मौजूद हैं। नवीनतम संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*The Queston was actually asked in the floor of the House by Shri.Md. Salim.